(a) whether substandard wheat, sugar, rice, palmolein etc. are distributed by the Food Corporation of India to the customers through Fair Price Shops in Gujarat;

(b) whether it is also a fact that sugar is not available at the ration shops now-a- days;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what action Government have taken or propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d). WHEAT AND RICE: Wheat and Rice supplied by Food Corporation of India from its godowns/depots to the State Governments and their nominees for Public Distribution System (PDS) conform to the P.F.A. specifications. The stocks are issued after that State Governments' nominees satisfy themselves both about the quality and quantity. No complaint has been received from Government of Gujarat regarding sub-standard foodgrains supplied by FCI for PDS in Gujarat.

PALMOLEIN: Palmolein is supplied by the State Trading Corporation of India to the State Governments including Gujarat against allocations made by Government of India for P.D.S. and no complaint about the quality thereof has been received either from the State Government or from any other quarter.

SUGAR: Food Corporation of India is not handling levy sugar in the State of Gujarat. It is the responsibility of the State Governments/ Union Territories to arrange for actual distribution of commodities lifted from F.C.I. and other Central Agencies to the Fair Price Shops and to supervise the distribution to consumers.

Surplus Foodgrains

4275. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item "Foodgrain surplus worries Centre" published in the "Tribune" of 9th August, 1994;

(b) if so, in view of the surplus foodgrains to the tune of 30.8 million tonnes, whether Government are still planning to dump more foodgrains by import; and

(c) whether Government will above remove restrictions on export of foodgrains?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir. Government has seen the news item.

(b) No, Sir.

(c) The policy of exports of foodgrains is reviewed on a continuous basis. It is decided keeping in view the demand/ supply position of the foodgrains.

गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य के सम्बन्ध में समिति

4276. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु मंत्री-स्तर की एक पांच सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी तथा सरकार को इसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने से पहले ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1 अगस्त, 1994 से गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है और प्रतिवेदन से पूर्व मूल्य वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की आर्थिक लागत में भी गत वर्षों की तुलना में निरन्तर वृद्धि की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो 1992-93 के वर्षों में गेहूं की आर्थिक लागत पृथक-पृथक कितनी थी तथा वर्ष 1994-95 में इसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) से (घ): गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि और भारतीय खाद्य निगम की हैंडलिंग लागत को आंशिक रूप से खपाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) में वृद्धि की जाती है। गेहूं का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य 402 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 1.2.1994 से प्रभावी है।

(ङ) और (च) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के लिए गेहूं की इकनामिक लागत निम्नानुसार है:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	इकनामिक लागत
1992-93	504.10
1993-94	559.40
1994-95 (बजट अनुमान)	563.57

बिहार में चीनी मिलें

4277. **श्री आस मोहम्मद:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी चीनी मिलें चलाई जा रही हैं;

(ख) इनमें से क्षेत्र-वार कितनी मिलें लाभ कमा रही हैं और कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) रुग्ण मिलों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सहकारी क्षेत्र की घाटे में चल रही चीनी मिलों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) बिहार में 30 संस्थापित चीनी मिलें हैं। इन 30 मिलों में से 15 गैर-सरकारी क्षेत्र और 15 सरकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) यह मंत्रालय चीनी मिलों से संबंधित लाभ और घाटे का कोई हिसाब नहीं रखता है।

(ग) चीनी मिलों को पुनर्वास/आधुनिकीकरण की योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं और उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन कराना होता है। ऐसी पुनर्वास/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस॰डी॰एफ॰) से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।

(घ) और (ङ) इस संबंध में नीति तैयार करना संबंधित रुग्ण चीनी मिलों/राज्य सरकारों का काम है।

Export of Foodgrains

4278. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the extent of the availability of foodgrains at present in Government godowns and under what consideration Government have taken a decision to export the same;

(b) whether Government had made any assessment about the profit or loss likely to be earned or incurred from the export of wheat before taking such a decision;

(c) if so, what are the details of the assessment made in this regard;

(d) whether Government would review the proposal regarding export of foodgrains in case the money earned through such export is likely to be less than the economic cost of Food Corporation of India;

(e) whether there is any proposal under Government's consideration to sell the surplus foodgrains through Public Distribution System to poor, backward and tribal regions of the country; and

(f) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d). The stock of foodgrains (wheat and rice) in Central Pool as on 1.7.1994 was as under:

(In lakh tonnes)

Wheat (P)	164
Rice (P)	133

(P) Provisional

No decision to export foodgrains from Central Pool has yet been taken.

(e) and (f) Already revamped Public Distribution System (RPDS) is in operation to distribute the foodgrains among the poor, backward and tribal regions of the country at a specially subsidised rate which is less by Rs. 50/- per quintal than the rate prescribed for normal PDS.

Setting up of Sugar Factories in Co- operative Sectors

4279. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD be pleased to state: